

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का ग्रामीण विकास में योगदान

(म.प्र. के सतना जिले के संदर्भ में)

रेनू शुक्ला

शोधार्थी वाणिज्य

शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, (म.प्र.)

सारांश :-

आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण अन्तर्संबंध (कनेक्टिविटी) बहुत प्रभावी है, खासकर भारत में, जहाँ 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य मुख्य मार्ग बिना जुड़े गाँवों को हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़क (कनेक्टिविटी) देना है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के असर का मूल्यांकन करता है, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करते थे, साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की भी पहचान की गई है। अध्ययन में द्वितीय सांख्यिकीय स्रोतों का उपयोग करके, अध्ययन में पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर आर्थिक अवसर बढ़ाए हैं, और बाज़ार के जुड़ाव को मज़बूत किया है। हालाँकि, भौगोलिक बाधाएँ, बजट की कमी, नौकरशाही में देरी और अपर्याप्त रखरखाव जैसी बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लंबी अवधि की प्रभावशीलता से उन्नत भौगोलिक योजना, बढ़ी हुई फंडिंग, बेहतर निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। ग्रामीण सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने से क्षेत्रीय अंतर को कम



करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने अन्य कम सेवा वाले क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी।

शब्द बीज:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, ग्रामीण विकास, सतना ज़िला, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास

प्रस्तावना:-

ग्रामीण अन्तर्संबंध (कनेक्टिविटी) आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और गरीबी कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में, जहाँ 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, खासकर सड़क (कनेक्टिविटी), सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ग्रामीण भारत में सड़कों परिवहन का मुख्य साधन हैं, जो रोज़मरा की ज़िंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और रोज़गार के अवसर शामिल हैं। हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों की कमी ग्रामीण समुदायों को अलग-थलग कर देती है, जिससे बाज़ारों, सरकारी सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और ज़रूरी सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है।

बेहतर ग्रामीण सड़क आधार भूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की ज़रूरत को पहचानते हुए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक लक्ष्य मैदानी इलाकों में कम से कम 500 और पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले बिना जुड़े गांवों को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरदराज

के गांवों को शहरी केंद्रों, बाजारों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं से जोड़कर ग्रामीण गतिशीलता में सुधार करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। राज्य सरकारों के कोर नेटवर्क सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना कार्यक्रम में लगभग 1.67 लाख बिना जुड़े घर शामिल हैं। इस परियोजना में नई कनेक्टिविटी के लिए 3.71 लाख किमी सड़कों का निर्माण और 3.68 लाख किमी सड़कों का उन्नयन शामिल है। भारत में ग्रामीण सड़कों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़कों शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करती हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना से लाभान्वित जिलों में, मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र में स्थित सतना जिले में अपनी भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण अलग पहचान रखता है। सतना अपनी पथरीली भूमि, सीमित जल संसाधनों और वर्षा आधारित कृषि पर भारी निर्भरता के लिए जाना जाता है। इस जिले ने ऐतिहासिक रूप से खराब बुनियादी ढांचे, कम कृषि उत्पादकता और सीमित रोजगार के अवसरों से संघर्ष किया है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गरीबी दर और मौसमी प्रवासन होता है। सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना के कार्यान्वयन ने परिवहन नेटवर्क में सुधार और आर्थिक अवसर पैदा करके इन चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण सङ्क कनेक्टिविटी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करती है और ग्रामीण समुदायों में गरीबी कम करती है।

साहित्य समीक्षा

सामंता, (2015)] के अध्ययन में बताया है कि 73वां संशोधन, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 में लागू हुआ। ग्रामीण विकास का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ग्रामीण परिवारों के लिए आय बढ़ाना

और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा वितरण प्रणालियों में सुधार करना है। PRI ने कई विकास पहल शुरू की हैं। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में मनरेगा, पीएमजीएसवाई, एसजीएसवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना शामिल हैं। कुछ परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण जलविद्युत मिशन द्वारा वित्त पोषित हैं।

ट्रैडस एट अल., (2015) के अध्ययन का मकसद यह पता लगाना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना सतना में आर्थिक विकास और ग्रामीण विकास को कैसे प्रभावित करता है। यह आकलन करता है कि बेहतर सङ्क कनेक्टिविटी कृषि, बाजार तक पहुंच, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समग्र जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना से पहले और बाद की दोनों स्थितियों की जांच करके, यह स्टडी कम सुविधा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण सङ्क विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है और भविष्य में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है।

बालमुरुगन, (2020) ने अध्ययन में यह पता लगाने की कोशिश किया है कि इस प्रोग्राम ने गैर-खेती वाले मजदूरों के लिए इनकम और रोजगार के मौके बढ़ाने में कितना असर डाला है और किस हद तक मदद की है। अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना का लोगों के रोजगार और इनकम के मौकों पर काफी असर पड़ा है। यह स्टडी ग्रामीण रोजगार और इनकम में रोड कनेक्टिविटी की भूमिका को समझने में हमारी मदद करेगी।

(ट्रैडस एट अल., 2015) ने मध्य प्रदेश के सेंट्रली फाइनेंशियल और फिजिकल का अध्ययन किया है। MNREGS और प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को स्पॉन्सर किया गया। CAGR के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि MGNREGS और प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना और MGNREGS ने अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा किया, लेकिन कई व्यवस्थित और परिचालन मुद्दों के कारण वे अपने इच्छित परिणामों से पीछे रह गए।

इंदिरा, (2023) भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हुए भारत की सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा प्रस्तुत करती है। अध्ययन में ग्रामीण विकास और सरकार की भूमिका की गयी है। (अनवरुज्जमां, 2018) PMGSY सङ्क ने जुड़े हुए गांवों की सामाजिक, भौतिक, वित्तीय और मानव पूँजी में सुधार किया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया गया है। यह अध्ययन मैहर, बाबूपुर, मङ्गिगवां प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना सङ्क का पड़ोसी गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव की जांच करता है। यह एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना कैसे समाज और अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।

सामंत, (2015) ने भारत में ग्रामीण सङ्कों के विकास का अध्ययन किया, 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 69% आबादी रहती है, जिससे आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है। बेहतर ग्रामीण सङ्क बुनियादी ढांचा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है, स्थायी गरीबी में कमी को बढ़ावा देता है, और औद्योगीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह अनुमान है कि अपर्यास सङ्कों के कारण 20-30% कृषि और वन उपज बर्बाद हो जाती है, जिससे परिवहन में बाधा आती है। ग्रामीण सङ्कों भारत के कुल सङ्क नेटवर्क का 60% हिस्सा हैं, जिसमें ग्रामीण सङ्क की लंबाई 1970-71 में 3,54,530 किमी से बढ़कर आज लगभग 24,50,559 किमी हो गई है। ग्रामीण सङ्कों में सार्वजनिक निवेश ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, जिससे स्थानीय समुदाय के विकास, कृषि मजदूरी और सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। हालांकि, भारत में ग्रामीण सङ्क विकास के प्रभाव पर अध्ययन सीमित हैं।

राव, (2019) भारत में तीन प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया है। प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक 1 करोड़ घर

बनाना था, जिसमें 2017-18 में 44.54 लाख घर पूरे हो गए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना में सङ्क निर्माण में काफी बढ़ोतरी देखी गई, 2017-18 में हर दिन 134 किमी सङ्कों बनीं, जो 2011-2014 के 73 किमी के औसत से 93% ज्यादा था। 2017-18 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने 5.12 करोड़ परिवारों को 234.25 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति-दिन का रोजगार दिया, जिससे 177 लाख नौकरियाँ मिलीं। ये योजनाएँ भारत के ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

मुखर्जी, (2013) गाँवों में नई बारहमासी सङ्कों बनाने के लिए पात्रता नियम के तहत सङ्क का लाभ उठाने के लिए कम से कम 500 लोगों की आबादी ज़रूरी थी, जिसके परिणामस्वरूप आबादी के आकार और सङ्कों की संख्या के बीच एक नॉन-लीनियर संबंध बना। सङ्क निर्माण के समय और छात्रों के नामांकन को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करने के लिए, अध्ययन आबादी की पात्रता को एक संकेतक के रूप में उपयोग करता है। आबादी की कटऑफ के दोनों ओर के गाँवों में स्कूल नामांकन की तुलना करके, अध्ययन में पाया गया कि बेहतर सङ्कों के माध्यम से स्कूलों तक बेहतर पहुँच से 2009 में नामांकन में 22% की वृद्धि हुई। 2002 में कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया, जब गाँवों में सङ्कों नहीं थीं। नामांकन पर प्रभाव उम समूह और जाति के अनुसार अलग-अलग होता है।

कुमार, (2011) ने अपने अध्ययन मैंइस विषय पर प्रकाश डाला है कि यह जाँच करता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के तहत बनी ग्रामीण सङ्कों ने ग्रामीण समुदायों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को कैसे बेहतर बनाया। अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण किसान कैसे उनकी खेती प्रणालियों को बेहतर बनाना और उनकी आय बढ़ाना।

जैन, (2014) ने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप

से ग्रामीण सड़कों पर केंद्रित है। गांवों में सड़कें बनाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य ग्रामीण आय को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। यह विकास गांवों, राज्यों और राष्ट्रों के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सड़कों ने जुड़े हुए गांवों में सामाजिक, भौतिक, वित्तीय और मानव पूँजी में वृद्धि की है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण प्रगति और राष्ट्रीय विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित हुआ है। यह भारत की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी वेबसाइटों और वार्षिक रिपोर्टों से माध्यमिक डेटा के आधार पर भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की जांच करता है। यह ग्रामीण विकास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और DDUGKY के महत्व पर जोर देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने 29.3 करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं; PMAY-G ने 2.2 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 1.40 करोड़ लोगों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर दिए हैं; और DDU-GKY योजना ने 11.12 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 6.48 लाख को नौकरियां मिली हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन की सीमा का विश्लेषण करना।
- सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

अनुसंधान पद्धति

मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र में सतना जिला, अपने ग्रामीण, पहाड़ी इलाके के लिए जाना जाता है। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में बदलाव देखे गए हैं, जिससे यह ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक आदर्श केस स्टडी बन गया है। माध्यमिक स्रोतों ने सतना क्षेत्र पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रभाव पर अध्ययन सामग्री प्रदान किया। यह अध्ययन बुनियादी ढांचे में सुधार और उनके सामाजिक-आर्थिक परिणामों की जांच करके सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन की सीमा और चुनौतियों की जांच करता है। अध्ययन सामग्री कई तरह के सोर्स से इकट्ठा किया गया था, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्रेस रिकॉर्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, अखबार और मैगज़ीन शामिल हैं। इस सेकेंडरी डेटा से सड़क निर्माण प्रोजेक्ट की स्थिति, लागू करने के दौरान आने वाली लॉजिस्टिकल और भौगोलिक चुनौतियों, और हेल्थकेयर, शिक्षा और बाजारों जैसी ज़रूरी सेवाओं तक स्थानीय निवासियों की पहुंच पर बेहतर कनेक्टिविटी के कुल असर पर रोशनी पड़ी। इसके अलावा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लंबे समय तक चलने की संभावना, साथ ही सतना के ग्रामीण और पहाड़ी इलाके की खास क्षेत्रीय चुनौतियों का आकलन करने के लिए सरकार की रिपोर्ट और आधिकारिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डॉक्यूमेंटेशन से सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया गया था।

सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति

मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र में स्थित सतना जिला, अपनी कठिन भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें पहाड़ी इलाका, घने जंगल और बिखरे हुए ग्रामीण गाँव शामिल हैं। ये

भौगोलिक बाधाएँ, गरीबी और सीमित बुनियादी ढाँचे जैसी सामाजिक-आर्थिक कारकों के साथ मिलकर, ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के विकास में बाधा बनी हुई हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 2000 में शुरू की गई थी, ने ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करके और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की। सतना में, यह पहल पहले से अलग-थलग पड़े गाँवों को जोड़ने, पहुँच में सुधार करने और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है।

1. सड़क निर्माण और विस्तार: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सतना के ग्रामीण सड़क बुनियादी ढाँचे में काफी सुधार हुआ है। हाल के अपडेट के अनुसार, 500 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों बनाई गई हैं, जो दूरदराज के गाँवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ती हैं और लोगों और सामान की आसान आवाजाही की अनुमति देती हैं। ये सड़कों सभी मौसम की स्थितियों का सामना करने के लिए बनाई गई हैं, जो मानसून के मौसम में भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती हैं, जब पारंपरिक रास्ते दुर्गम हो जाते हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण निवासियों के यात्रा के समय में काफी कमी आई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँचना आसान हो गया है।

2. लाभान्वित गाँव: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने सतना जिले के 150 से अधिक गाँवों को प्रभावित किया है। इनमें से कई गाँव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होने से पहले पर्याप्त सड़कों की कमी के कारण मुख्य शहरी केंद्रों से कटे हुए थे। बेहतर कनेक्टिविटी ने न केवल किसानों और कारीगरों को बेहतर बाजार तक पहुँच प्रदान की है, बल्कि इसने सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ाया है, जिससे निवासी अब सामुदायिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में अधिक आसानी से भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी ने सरकारी कार्यक्रमों और संसाधनों तक पहुँच में सुधार किया है, जिससे ग्रामीण आबादी की समग्र भलाई में सुधार हुआ है।

3. फंडिंग और कार्यान्वयन: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सतना जिले में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के समर्थन से सफलतापूर्वक लागू किया गया था। फंडिंग संरचना सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ढांचे का पालन करती है, जिसमें केंद्र सरकार वित्तीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है और राज्य और स्थानीय सरकारें क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर फंडिंग को पूरक बनाती हैं। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से आने वाली लॉजिस्टिक्स चुनौतियों से निपटने में सरकार के अलग-अलग लेवल के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फंडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से नई सड़कें बनाने, मौजूदा रास्तों को अपग्रेड करने और दूर-दराज के गांवों में सड़कों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा, फंड का एक हिस्सा स्थानीय समुदाय की ट्रेनिंग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि सड़क बनने के बाद वे उसके रखरखाव और टिकाऊपन में शामिल हो सकें।

4. स्थानीय समुदायों पर प्रभाव: बेहतर सड़क नेटवर्क ने ग्रामीण समुदायों को बदल दिया है। ग्रामीण निवासियों को अब बाजारों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से पहुंच मिल गई है। इससे आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है, खासकर किसानों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए जो अब अपने उत्पादों को बड़े बाजारों में बेच सकते हैं। इसके अलावा, बेहतर सड़कों ने महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गतिशीलता बढ़ाई है, जिससे वे सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में अधिक आज़ादी से भाग ले सकते हैं।

सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की सीमा- सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का परिचय: मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र का एक जिला, सतना, अपनी ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और उच्च ग्रामीण जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है। जिले की भौगोलिक

विशेषताएं, जैसे पहाड़ी इलाका, बिखरी हुई बस्तियाँ, और अविकसित बुनियादी ढाँचा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करना मुश्किल बनाते हैं। इन बाधाओं के बावजूद, PMGSY ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिली है।

सड़क निर्माण और उन्नयन: 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना के बाद से, सतना में सड़क निर्माण और उन्नयन में महत्वपूर्ण निवेश देखा गया है। कार्यक्रम का प्रारंभिक ध्यान दूरदराज के गाँवों तक सभी मौसम में चलने वाली सड़कों बनाने पर था, जिनमें से कई पहले पहुँच से बाहर थे, खासकर मानसून के मौसम में। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने सतना की लगभग 65% ग्रामीण सड़कों का निर्माण या उन्नयन किया है। उदाहरण के लिए, कई गाँव जो पहले खराब सड़क स्थितियों के कारण अलग-थलग थे, अब आस-पास के कस्बों से बेहतर ढंग से जुड़े हुए हैं, जिससे निवासियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में मदद मिलती है। पहले, इन गाँवों के निवासियों को इन सेवाओं तक पहुँचने के लिए अक्सर कठिन इलाकों से होकर लंबी दूरी पैदल चलना पड़ता था। सभी मौसम में चलने वाली सड़कों की शुरुआत से यात्रा का समय काफी कम हो गया है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि, जिले में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सड़क कनेक्टिविटी अपर्याप्त है। ये क्षेत्र, जो अक्सर जिले के अधिक कठिन इलाकों में स्थित हैं, अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बुनियादी ढाँचे तक पूरी पहुँच नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण परियोजना पूरी होने में देरी हो रही है, जो जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन में असमानता को उजागर करता है।

- पहुँच पर प्रभाव:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन से सतना जिले में पहुँच में काफी सुधार हुआ है। सड़कों के उन्नयन से पहले, जिले के कई गाँव बरसात के मौसम में कट

जाते थे, जिससे आवाजाही और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती थी। आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने के लिए, ग्रामीणों को अस्थायी सड़कों, पशु गाड़ियों का उपयोग करना पड़ता था, या पैदल चलना पड़ता था। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ, सतना जिले के निवासी अब अधिक स्वतंत्र रूप से और कुशलता से यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक्सेसिबिलिटी पर इन तरीकों से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

- **शिक्षा तक पहुँच:** बेहतर सड़कों के कारण, छात्र अब नियमित रूप से स्कूल जा सकते हैं। सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों के निर्माण से पहले, लंबी दूरी की यात्रा में कठिनाई के कारण स्कूल में उपस्थिति बाधित होती थी, खासकर दूरदराज के गांवों में रहने वाले छात्रों के लिए। इन गांवों को पास के कस्बों से जोड़ने वाली सड़कों के कारण, छात्र अब अधिक नियमित रूप से स्कूल जा सकते हैं, और नामांकन में वृद्धि हुई है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** बेहतर सड़कों के कारण, जिले की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अधिक सुलभ हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अब अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक तेज़ी से पहुँच सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप होता है। आपातकालीन मामले, जिनमें पहले लंबा यात्रा समय लगता था, अब स्वास्थ्य सुविधाओं तक अधिक तेज़ी से पहुँच सकते हैं, जिससे संभावित रूप से जान बचाई जा सकती है।
- **बाजारों तक पहुँच:** बेहतर सड़कें किसानों और छोटे पैमाने के कारीगरों को अपने उत्पाद स्थानीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर आर्थिक परिणाम मिलते हैं। पहले, इन ग्रामीण क्षेत्रों के अलगाव ने निवासियों की वाणिज्य में शामिल होने की क्षमता को सीमित कर दिया था। स्थानीय व्यवसाय कनेक्टिविटी बेहतर होने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बड़ी अर्थव्यवस्था में ज्यादा इंटीग्रेट होने से विकास हो सकता है।

- **पूरा होने की स्थिति और बाकी कमियां:** काफी तरक्की होने के बावजूद, सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को पूरी तरह से लागू करने में कई कमियां हैं। कुछ गांव, खासकर पहाड़ी इलाकों या मुश्किल पहुंच वाले इलाकों में, अभी भी सही सङ्क बनने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, जिले में अचानक आई मुश्किलों की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है, जिससे सङ्क प्रोजेक्ट के पूरे होने में अंतर आया है। इसके अलावा, कुछ इलाकों में सङ्कों का आधा-अधूरा निर्माण हुआ है, और कुछ हिस्से अधूरे रह गए हैं। इससे ऐसी स्थिति बनती है जहां लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से कभी-कभार ही फायदा होता है, जिससे निराशा होती है और प्रोग्राम का पूरा पोटेंशियल पाने में देरी होती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को लागू करने में चुनौतियां-

सङ्क निर्माण में अपनी सफलताओं के बावजूद, सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को लागू करने में कई चुनौतियां आई हैं। इन चुनौतियों में ज्योग्राफिकल रूकावटें, लॉजिस्टिक दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कतें और प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी शामिल हैं।

- **मुख्य चुनौतियाँ:** ज्योग्राफिकल चुनौतियाँ: सतना जिला एक ऐसे इलाके में है जहाँ पहाड़ी इलाके और बाढ़ आने वाले इलाके मुश्किल हैं।
- बघेलखण्ड इलाका, जिसमें सतना भी शामिल है, अपनी मुश्किल टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, जिससे सङ्क बनाने का काम मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में, इन इलाकों में सङ्क बनाने के लिए भारी मशीनरी, बहुत ज़्यादा खुदाई और घाटियों या पानी की जगहों को पार करने के लिए पुल बनाने जैसी खास तकनीकों की ज़रूरत होती है।
- मानसून का मौसम इन दिक्कतों को और बढ़ा देता है, क्योंकि भारी बारिश से अक्सर बाढ़ आती है जिससे बिना सुरक्षा वाली सङ्कों टूट जाती हैं और बनने में देरी होती है। सतना के पहाड़ी

इलाकों में अक्सर लैंडस्लाइड होते हैं, जिससे चल रहे प्रोजेक्ट्स में रुकावट आती है और सड़क का मैटेनेंस मुश्किल हो जाता है। इससे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना खास तौर पर मुश्किल हो जाता है जो लंबे समय तक चले।

- **लॉजिस्टिक दिक्कतें:** सतना के गांव वाले इलाके होने की वजह से, लॉजिस्टिक दिक्कतें की वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट्स को आसानी से पूरा करने में दिक्कतें आती हैं। सीमेंट, स्टील और बजरी जैसे कंस्ट्रक्शन मटीरियल को दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए अक्सर कच्चे या मुश्किल रास्तों से लंबा सफर तय करना पड़ता है। इन इलाकों में भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से हालात और खराब हो जाते हैं। लोकल कॉन्ट्रैक्टर, जिन्हें अक्सर सड़कें बनाने का काम सौंपा जाता है, उन्हें मटीरियल ढूँढने और सप्लाई चेन को मैनेज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूर-दराज के इलाकों में सड़कें बन रही हैं, इसलिए ज़रूरी सामान पहुंचाना महंगा और समय लेने वाला हो जाता है। इस लॉजिस्टिक चुनौती की वजह से प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में काफी देरी हुई है।
- **फंडिंग और बजट की कमी:** सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में एक और बड़ी चुनौती फंडिंग का कम होना है। हालांकि केंद्र सरकार गांव की सड़कों को बनाने के लिए बजट देती है, लेकिन यह फंडिंग अक्सर सड़क बनाने के पूरे खर्च को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती, खासकर मुश्किल इलाकों में। बजट की कमी के कारण सतना में कई सड़कें अधूरी रह गई हैं।

रख-रखाव और सुरक्षा -

- कुछ पर सिर्फ शुरुआती ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, सड़क रखरखाव के लिए पर्याप्त फंडिंग की कमी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें पहले ही खराब होने

लगी हैं, जिससे कार्यक्रम की कुल उपयोगिता कम हो रही है। उचित रखरखाव के बिना, सङ्कें जल्दी ही बेकार हो जाती हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फायदे खत्म हो जाते हैं।

- **कार्यान्वयन में देरी:** सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सङ्क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी रही है। जिले में कई सङ्क परियोजनाएं नौकरशाही की अक्षमताओं, ठेकेदार की समस्याओं और स्थानीय बाधाओं के कारण अपनी मूल समय-सीमा से आगे निकल गई हैं।
- **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नौकरशाही में देरी** आम बात है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना भी शामिल है। धीमी निर्णय प्रक्रिया, लालफीताशाही और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की समस्याओं के कारण काफी देरी हुई है। कुछ मामलों में, स्थानीय ठेकेदारों को अनुबंध प्रबंधन समस्याओं, कार्यस्थल में रुकावटों और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे प्रगति धीमी हुई है।

अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन:

एक और बड़ी समस्या एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की कमी रही है। कई मामलों में, स्थानीय प्रशासनिक निकाय PMGSY परियोजनाओं पर काम की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने में असमर्थ रहे हैं। नतीजतन, सङ्कें घटिया मानकों पर बनाई जाती हैं या अधूरी छोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा, समय पर ऑडिट या मूल्यांकन की कमी से कार्यक्रम के निष्पादन में अक्षमताएं आई हैं।

सुझाव-

सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, निम्नलिखित सिफारिशों की जाती हैं: बेहतर भौगोलिक योजना: सतना की जटिल भौगोल को देखते हुए, कठिन इलाके से निपटने के लिए उन्नत योजना और इंजीनियरिंग तकनीकों की आवश्यकता है। सड़क निर्माण के लिए सबसे कुशल मार्गों का नक्शा बनाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सड़कों सबसे अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से बनाई जाएं। इसके अलावा, लंबे समय तक सफलता के लिए ऐसी सड़कों बनाना जो कठोर मौसम की स्थिति का सामना कर सकें, महत्वपूर्ण है।

कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन: लॉजिस्टिक्स समस्याओं को दूर करने के लिए, स्थानीय सरकारों को सड़क निर्माण सामग्री के लिए परिवहन और आपूर्ति शृंखला प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। क्षेत्रीय आपूर्ति डिपो स्थापित करने और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी करने से परिवहन लागत को कम करने और सामग्री वितरण दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर प्राप्त सामग्री और श्रम का उपयोग करने से परिवहन लागत कम हो सकती है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है।

बढ़ा हुआ फंडिंग आवंटन: केंद्र और राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। मुश्किल इलाकों में सड़क निर्माण के लिए ज्यादा बजट अलॉट करने से चल रहे प्रोजेक्ट पूरे होंगे और अलग-थलग इलाकों में सड़कों बनेंगी। इसके अलावा, लंबे समय तक टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए सड़क रखरखाव के लिए एक समर्पित फंड स्थापित किया जाना चाहिए।

निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करना: यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट सहमत समय-सीमा और स्पेसिफिकेशन्स के भीतर पूरे हों। थड़-पार्टी ऑडिट और स्थानीय समुदाय भागीदारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि ठेकेदार प्रोजेक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करें और सड़कें अच्छी तरह से मेंटेन रहें। फंड आवंटन में पारदर्शिता, साथ ही रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, जवाबदेही बढ़ाने में मदद कर सकती है।

कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि सड़कें ग्रामीण आबादी की वास्तविक जरूरतों को पूरा करें। सामुदायिक भागीदारी स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे सड़क रखरखाव में सुधार होगा। स्थानीय मजदूरों को ट्रेनिंग देने और स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट की लागत कम होगी।

समय पर निर्णय लेना और समन्वय: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए, स्थानीय सरकारों को अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार करने और नौकरशाही अक्षमताओं को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट के चरणों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना और देरी के लिए हितधारकों को जवाबदेह ठहराना सड़क निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को कम करने में मदद कर सकता है।

हालांकि इस अध्ययन का उद्देश्य सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है, फिर भी कई सीमाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये सीमाएँ निष्कर्षों की सामान्यीकरण, सटीकता और पूर्णता पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन बाधाओं को पहचानना अध्ययन के दायरे को समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए

महत्वपूर्ण है जहां अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है। भौगोलिक दायरा: अध्ययन की प्राथमिक सीमाओं में से एक इसका भौगोलिक फोकस है। यह पेपर देखता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सतना जिले में कैसे लागू किया जा रहा है, जो मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र में है। हालांकि सतना ग्रामीण भारत का एक प्रतिनिधि मामला है, जिसमें अपनी चुनौतियाँ और अवसर हैं, लेकिन निष्कर्ष अन्य जिलों या राज्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं। पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की एक विस्तृत शृंखला है, जो सभी ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावशीलता पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, पहाड़ी इलाके, वन क्षेत्र, या घनी आबादी वाले क्षेत्र सड़क निर्माण के लिए अद्वितीय चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं जो सतना में कम स्पष्ट हैं।

नतीजतन, अध्ययन के निष्कर्षों की अलग-अलग स्थलाकृति, जलवायु और बुनियादी ढांचा चुनौतियों वाले अन्य क्षेत्रों में सीमित प्रयोज्यता हो सकती है। भविष्य का शोध विश्लेषण के दायरे को विभिन्न क्षेत्रों के कई जिलों को शामिल करने के लिए व्यापक कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विविध ग्रामीण संदर्भों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन की अधिक पूर्ण समझ होगी। सीमित डेटा उपलब्धता: एक और कमी सेकेंडरी डेटा सोर्स जैसे सरकारी रिपोर्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रिकॉर्ड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल है। हालांकि ये दस्तावेज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहल की आधिकारिक प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन वे हमेशा अप-टू-डेट या पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट, जो आमतौर पर सालाना या दो साल में एक बार प्रकाशित होती है, कभी-कभी ज़मीनी स्तर पर होने वाले वास्तविक समय के विकास, विसंगतियों या चुनौतियों को दर्शाने में विफल हो सकती हैं। इसके अलावा, हालांकि सरकारी डेटा आम तौर पर व्यापक होता है, लेकिन

इसमें यह समझाने के लिए विस्तृत संदर्भ की कमी हो सकती है कि कार्यान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं।

सामयिक बाधाएँ: यह अध्ययन सतना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन की स्थिति को देखता है यह स्टडी किसी खास समय पर ज़िले में होने वाले कामों के बारे में जानकारी देती है। हालांकि यह प्रोग्राम की प्रोग्रेस के बारे में काम की जानकारी देती है, लेकिन यह ग्रामीण विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं पर सड़कों के लंबे समय के असर को दिखाने में नाकाम हो सकती है। सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर का असर दिखने में सालों लग सकते हैं, खासकर जब लोकल इकॉनमी, सामाजिक व्यवहार, माइग्रेशन पैटर्न और क्षेत्रीय विकास में लंबे समय के बदलावों को ध्यान में रखा जाता है। यह देखते हुए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक चालू प्रोजेक्ट है, स्टडी में हाल के डेवलपमेंट या भविष्य के बदलाव छूट सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेनेबिलिटी और टिकाऊपन पर असर डालेंगे। फाइनेंशियल और टेक्निकल डेटा की कमी: इस स्टडी की एक और कमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट्स के डिटेल्ड फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस की कमी है।

यह अध्ययन कार्य योजना के क्वालिटेटिव पहलुओं पर फोकस करता है, लेकिन यह कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान आने वाले फाइनेंशियल मैकेनिज्म, बजटिंग और टेक्निकल चुनौतियों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताता है। उदाहरण के लिए, सड़क बनाने, मैटेनेंस और मॉनिटरिंग के लिए फंड के एलोकेशन की पूरी जांच से ज़िले की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फाइनेंशियल वायबिलिटी और स्टेनेबिलिटी पर रोशनी पड़ सकती है। इसी तरह, टेक्निकल चुनौतियों—जैसे मटीरियल चुनना, सड़क का डिज़ाइन और बनाने के तरीके—की गहराई से जांच करने से उन वजहों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और लंबे समय तक चलने पर असर डालती हैं। इन बातों को शामिल करने से प्रोग्राम की चुनौतियों और सफलताओं के

बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य के पॉलिसी फैसलों और प्लानिंग के लिए काम आएगी।

लागू करने में कमियां: हालांकि यह स्टडी प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों का एक ओवरव्यू देती है, लेकिन यह प्रोसेस में सभी कमियों को ध्यान में नहीं रख सकती है। यह स्टडी खास समुदायों या गांवों को प्रभावित करने वाले छोटे लेवल के मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ सङ्कें बन गई होंगी लेकिन वे बड़े ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं, जिससे उनका असर कम हो जाता है। इसके अलावा, सङ्कों की क्वालिटी एक जगह से दूसरी जगह बहुत अलग हो सकती है, कुछ इलाकों में घटिया कंस्ट्रक्शन या मैटेनेंस की कमी देखी जा सकती है। यह पेपर बड़े लेवल पर चुनौतियों को बताता है, लेकिन यह लोकल लेवल पर लागू करने में कमियों की खास बातों को नज़रअंदाज़ कर सकता है जो ग्रामीण आबादी को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। आगे की रिसर्च में गांव के लेवल पर केस स्टडी की जा सकती है ताकि माइक्रो लेवल की कमियों का पता लगाया जा सके।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में ग्रामीण सङ्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक तरक्की को बढ़ावा मिला है। हर मौसम में चलने वाली सङ्कें देकर, इस प्रोग्राम ने हेल्थकेयर, शिक्षा, बाज़ार और नौकरी के मौकों तक पहुंच को बेहतर बनाया है, जिससे ग्रामीण समुदाय का अकेलापन कम हुआ है। इससे खेती की पैदावार बढ़ी है, बाज़ार बेहतर तरीके से जुड़ा है और जिले के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हुई है। अपनी सफलताओं के बावजूद, प्रोग्राम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो इसके पूरे असर को रोकती हैं।

सतना जिला का ऊबड़-खाबड़ इलाका और भौगोलिक रुकावटें बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं।

जिले का पहाड़ी इलाका और बिखरी हुई बस्तियां सड़क बनाने को मुश्किल बनाती हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से आमतौर पर मानसून के मौसम में नई बनी सड़कों को नुकसान पहुंचता है, जिससे बार-बार मरम्मत और मैटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा, कुछ गांवों के दूर-दराज होने की वजह से कंस्ट्रक्शन मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करना लॉजिस्टिकली मुश्किल हो गया है, जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है। ये ज्योग्राफिकल और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लागू होने की गति धीमी हो गई है, जिससे कुछ इलाके बिना जुड़े रह गए हैं या उनके सड़क नेटवर्क अधूरे हैं। फंडिंग की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को केंद्र सरकार से फंड मिलता है, लेकिन सड़क निर्माण और लंबे समय तक रखरखाव की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बजट आवंटन अक्सर अपर्याप्त रहा है। बजट की कमी के कारण कुछ सड़कें आंशिक रूप से अधूरी रह गई हैं, जबकि अन्य सड़कों का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ है, जिससे उनकी टिकाऊपन कम हो गई है। एक समर्पित रखरखाव फंड के बिना, जो सड़कें कनेक्टिविटी का फायदा देती हैं, वे समय के साथ खराब हो सकती हैं, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुई प्रगति उलट जाएगी।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा नौकरशाही की अक्षमता, धीमी निर्णय लेने की प्रक्रिया और सरकारी एजेंसियों के बीच खराब समन्वय के कारण होने वाली देरी है। स्थानीय सड़क निर्माण ठेकेदारों को सप्लाई चेन में रुकावट, मजदूरों की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे प्रोजेक्ट की समय-सीमा उम्मीद से ज्यादा हो गई है। इन देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण समुदाय समय पर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाने से भी वंचित रह जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सतना में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 150 से अधिक गांवों को जोड़ा गया है, जिससे किसानों, छात्रों और स्थानीय

व्यवसायों के लिए आवाजाही बढ़ी है। छात्रों को अब स्कूलों तक आसानी से पहुंच मिल गई है, जिससे उनके शैक्षिक अवसरों में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं अब अधिक सुलभ हो गई हैं, जिससे अस्पतालों तक यात्रा का समय कम हुआ है और आपातकालीन प्रतिक्रिया दक्षता में सुधार हुआ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हुआ है क्योंकि बेहतर सड़कों ने किसानों और छोटे उद्यमियों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद की है, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्थिरता बढ़ी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए कुछ सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। GIS तकनीक का उपयोग करके उन्नत भौगोलिक योजना कुशल मार्गों को मैप करने और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से बचने में मदद कर सकती है। लंबी अवधि की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सड़क रखरखाव के लिए अधिक फंडिंग की आवश्यकता है। बेहतर निगरानी तंत्र, जैसे कि थर्ड-पार्टी ऑडिट, निर्माण की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और साथ ही भृष्टाचार और कुप्रबंधन को भी रोक सकते हैं।

अंत में, स्वामित्व की भावना पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि परियोजना पूरी होने के बाद भी सड़कों का ठीक से रखरखाव किया जाए। संक्षेप में, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने सतना में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लगातार चुनौतियों के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार इलाके, फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और परियोजना निष्पादन जैसे मुद्दों को संबोधित करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकती है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत कर सकती है। प्रभावी कार्यान्वयन से शहरी-ग्रामीण खाई को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे सतना समुदाय के लिए समावेशी विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

संदर्भ

1. अनवरुज्जमां, ए. के. एम. (2018). PMGSY का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव: चांदपुर-कुशाबरिया रोड, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल का एक केस स्टडी इंडो-बांग्ला एन्कलेव व्यू प्रोजेक्ट वेटलैंड पर्यावरण व्यू प्रोजेक्ट। 19(जुलाई), 31–39. <https://www.researchgate.net/publication/327070746>
2. दीपक RDS.pdf. (n.d.).
3. जैन, एम. पी. (2014). प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: मध्य प्रदेश के समावेशी विकास का एक मार्ग MP. 3(2), 2319–2828.
4. कुमार, बी. (2011). ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर PMGSY सड़कों का प्रभाव: जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले से साक्ष्य।
5. मुखर्जी, एम. (2013). क्या बेहतर सड़कें स्कूल में नामांकन बढ़ाती हैं? भारत में एक अद्वितीय सड़क नीति से साक्ष्य। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। <https://doi.org/10.2139/ssrn.2207761>
6. राव, पी. एस. (2019). भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं – एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज, 06(1), 1072–1076. <http://www.ijrar.org/papers/IJRAR19J1450.pdf>
7. इंदिरा, बी. (2023). Issn:2277-7881; i. 017(3), 63–66.
8. सामंत, पी. के. (2015). भारत में ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे का विकास। पैसिफिक बिजनेस रिव्यू इंटरनेशनल, 7(11), 86–93. http://www.pbr.co.in/2015/2015_month/May/12.pdf
9. ट्रैड्स, आर., ISBN, एम., पाटिल, एल. पी., और पाटिल, ए. एल. (2015). राज्य में ग्रामीण विकास में मनरेगा और पीएमजीएसवाई की भूमिका। 119–127।